

न्यूज़ टुडे

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में NavIC ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

ऑपरेशन के दौरान, भारत ने युद्ध अभियानों के कई स्तरों पर NavIC (नेविगेशन विद् इंडियन कॉन्स्टेलेशन) का उपयोग किया, जैसे- मिसाइल गाइडेंस, ड्रोन नेविगेशन, युद्ध क्षति आकलन, आदि।

NavIC के बारे में

- यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित एक स्वतंत्र स्टैंड-अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है।
 - इस प्रणाली को पहले IRNSS (भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली) के नाम से जाना जाता था।
 - भारत विकासशील विश्व का एकमात्र देश है, जिसने इस तरह की प्रणाली तैनात की है।
- कवरेज: यह प्रणाली भारत के संपूर्ण भूभाग के अलावा इसकी सीमाओं से 1,500 कि.मी. तक के क्षेत्र को कवर करती है। यह अवस्थिति, वेग और समय (Position, Velocity & Timing) संबंधी सेवाएं प्रदान करती है।
- सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन: इसमें 7 सैटेलाइट्स और 24 x 7 संचालित होने वाले ग्राउंड स्टेशनों का एक नेटवर्क शामिल है।
 - 3 सैटेलाइट्स भू-स्थैतिक कक्षा (Geostationary orbit) में तथा 4 झुकाव युक्त भू-तुल्यकालिक कक्षा (Geosynchronous orbit) में स्थापित हैं।
 - ये सैटेलाइट्स डब्ल्यू बैंड सिग्नल (L5 और S-बैंड) से लैस हैं।
 - L5 सिग्नल सैन्य उपयोग के लिए एन्क्रिप्टेड है।
- प्रमुख सेवाएं: यह नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए मानक अवस्थिति सेवा (Standard Position Service) और अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित सेवा (Restricted Service) प्रदान करती है।

स्वायत्त उपग्रह नेविगेशन सिस्टम वाले देश	
	संयुक्त राज्य अमेरिका - GPS
	रूस - ग्लोनास
	यूरोपीय संघ - गैलिलियो
	चीन - बेइदोउ

NavIC प्रणाली के सामरिक लाभ

- GPS पर निर्भरता को समाप्त करती है: भारत किसी विदेशी स्वामित्व वाले नेविगेशन सिग्नल पर निर्भर हुए बिना भी दुश्मन देश के अंदर तक हमला कर सकता है। 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान अमेरिका ने भारत को GPS सर्विस देने से इनकार कर दिया था।
- एन्क्रिप्टेड मिलिट्री चैनल: मिसाइल और ड्रोन मिशन के दौरान जैमिंग या स्फूर्फिंग को रोकती है।
- तीव्र गति से सिग्नल लॉक: भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में GPS से भी अधिक सटीकता प्रदान करती है।
- सामरिक बढ़त: NavIC की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए NVS (NavIC सेकंड जनरेशन सैटेलाइट) श्रृंखला का विस्तार किया जा रहा है। इसका लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र को और अधिक व्यापक रूप से कवर करना है।

NavIC के लिए भारत के दृष्टिकोण में शामिल हैं

- हाइपरसोनिक वेपन इंटीग्रेशन: भविष्य के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स (HGVs) को निर्देशित करना।
- स्पेस कमांड नेटवर्क: भारत की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, खुफिया, निगरानी और टोही (ISR) उपग्रहों तथा काइनेटिक स्पेस रिसॉन्स यूनिट्स के लिए डिजिटल आधार के रूप में कार्य करना।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाई-रिज़ॉल्यूशन 'भारत पूर्वानुमान प्रणाली' शुरू की

भारत पूर्वानुमान प्रणाली (BFS) को IMD में सफलतापूर्वक एकीकृत करने के बाद, भारत रियल टाइम में इतने हाई रिज़ॉल्यूशन पर वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली संचालित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। BFS को 6 किमी. ग्रिड रिज़ॉल्यूशन के साथ विकसित किया गया है।

भारत पूर्वानुमान प्रणाली (BFS) की मुख्य विशेषताएं

- स्वदेशी रूप से विकसित: यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे की महिला वैज्ञानिकों द्वारा विकसित अगली पीढ़ी का मौसम पूर्वानुमान मॉडल है।
 - IITM में नए सुपर कंप्यूटर अर्का की स्थापना से BFS के विकास में मदद मिली है।
- हाई-रिज़ॉल्यूशन फोरकास्ट सिस्टम: यह 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच अवस्थित उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए 6 किमी. रिज़ॉल्यूशन पूर्वानुमान प्रदान कर सकता है।
 - यूरोप, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संचालित ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम का रिज़ॉल्यूशन 9 किमी. और 14 किमी. के बीच है।
- स्थानीय पूर्वानुमान: यह पंचायत स्तर तक परिचालन पूर्वानुमान प्रदान करेगा। इससे देश में अत्यधिक वर्षा और अन्य स्थानीय मौसम की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
- सटीकता: इसमें 'ट्राइएंगुलर क्यूबिक ऑक्टोहेड्रल ग्रिड मॉडल' पर आधारित रियल टाइम मॉडलिंग का उपयोग किया जाता है। इससे चरम वर्षा संबंधी मौसमी घटनाओं के पूर्वानुमान में 30%--64% का सुधार देखा गया है।

डॉप्लर वेदर रडार (DWR)

- डॉप्लर वेदर रडार एक विशेष रडार होता है जो वर्षा, तूफान और चक्रवात जैसी मौसम प्रणालियों की गति एवं तीव्रता को ट्रैक करने के लिए डॉप्लर प्रभाव का उपयोग करता है।
 - डॉप्लर प्रभाव किसी तरंग (ध्वनि या प्रकाश) की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन को व्यक्त करता है। इसे तरंग के स्रोत के सापेक्ष गतिशील प्रेक्षक द्वारा अनुभव किया जाता है।
- यह विशेष रूप से चक्रवात जैसे गंभीर मौसम के लिए मौसम पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार करता है।

- यह एक निर्धारणात्मक मॉडल (Deterministic model) है, जो सिंगल-मॉडल आधारित आउटपुट उत्पन्न करता है। इसका अर्थ यह है कि यह संभावनाओं की एक श्रृंखला की बजाय एक निश्चित पूर्वानुमान प्रदान करता है।

- डॉप्लर वेदर रडार नेटवर्क: मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए 40 डॉप्लर वेदर रडार का राष्ट्रीय नेटवर्क एक मजबूत, भरोसेमंद एवं रियल टाइम इनपुट प्रदान करता है।

- डॉप्लर रडार की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाकर 100 कर दी जाएगी। इससे राष्ट्रीय नाउकास्ट यानी 2 घंटे का मौसम पूर्वानुमान सक्षम हो जाएगा।

ऑटोनोमस सैटेलाइट्स अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के नए युग की शुरुआत हुई

कई देश ऑटोनोमस सैटेलाइट्स के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

- 2024 में, चीन ने दुनिया के पहले “ऑटोनोमस सैटेलाइट” को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ये उपग्रह ग्राउंड स्टेशन आधारित हस्तक्षेपों के बिना स्वायत्त रूप से उड़ान पथ को बनाए रख सकते हैं या उसे बदल सकते हैं।

ऑटोनोमस सैटेलाइट के बारे में

- ये उपग्रह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों और एल्गोरिदम का उपयोग करके न्यूनतम या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपना कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
 - ये प्रौद्योगिकियां उपग्रहों को एक निष्क्रिय पर्यवेक्षकों से सक्रिय और विचारशील मशीनों में तब्दील कर रही हैं।
- उपग्रह में मौजूद इंटेलिजेंस को सैटेलाइट एज कंप्यूटिंग कहा जाता है। यह उपग्रह को अपने परिवेश का विश्लेषण करने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

प्रमुख उपयोग

- स्वचालित अंतरिक्ष परिचालन: इनका उपयोग डॉकिंग, निरीक्षण, कक्षा में ईंधन भरने और मलबा हटाने जैसे कार्यों के लिए अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु किया जा सकता है।
- स्व-निदान और मरम्मत: ये उपग्रह अपनी स्थिति की निगरानी कर गड़बड़ी की पहचान करके मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वयं मरम्मत कर सकते हैं।
- उड़ान पथ निर्धारित करना: ये खतरों और बाधाओं से बचने या ईंधन बचाने के लिए कक्षीय प्रक्षेप पथ को आवश्यकतानुसार समायोजित कर सकते हैं।
- स्थानीय भू-स्थानिक जानकारी जुटाना: पृथ्वी की कक्षा से वास्तविक समय में आपदाओं और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का पता लगाने तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए अन्य उपग्रहों के साथ जानकारी को साझा करने में मदद मिल सकती है।
- युद्ध या संघर्ष के दौरान सहयोग: ये वास्तविक समय में खतरे की पहचान कर सकते हैं तथा सीधे कक्षा से ऑटोनोमस रूप से टारगेट की ट्रैकिंग कर सकते हैं और उसे नष्ट करना सक्षम बनाते हैं।

ऑटोनोमस सैटेलाइट से जुड़ी प्रमुख चिंताएं

- AI संबंधी भ्रम: यह किसी उपग्रह को खतरे के रूप पहचानने में गलती कर सकता है। इससे उपग्रहों के बीच आकस्मिक टकराव का खतरा उत्पन्न हो सकता है।
 - AI संबंधी भ्रम एक ऐसी घटना है, जिसमें AI सिस्टम गलत धारणा बनाता है। यह तब होता है, जब AI कोई ऐसे पैटर्न या ऑब्जेक्ट को पहचानता है, जो वास्तव में मौजूद ही नहीं होता है।
- अंतरिक्ष संबंधी कानूनों में मौजूद खामियां: मौजूदा संधियां (जैसे बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967, देयता अभिसमय 1972 आदि) उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष मिशनों पर मानव नियंत्रण को मानक बनाती हैं।
- अन्य: साइबर खतरा, आदि।

नीति आयोग ने “मध्यम उद्यमों के लिए नीति तैयार करना” शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की

इस रिपोर्ट में MSME क्षेत्र के भीतर संरचनात्मक असंतुलन और मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही, इसमें इनकी अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप का सुझाव भी दिया गया है।

- MSME क्षेत्र (वर्गीकरण के लिए ग्राफिक देखें) सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29% का योगदान देता है। कुल निर्यात में इसकी 40% हिस्सेदारी है। साथ ही, यह 60% से अधिक कार्यबल को रोजगार भी प्रदान करता है।
 - हालांकि, इस क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की संख्या अधिक है, जो सभी पंजीकृत MSMEs का लगभग 97% हिस्सा है। इसके बाद लघु उद्यमों (2.7%) और मध्यम उद्यमों (0.3%) का स्थान आता है।
 - MSMEs में मध्यम उद्यमों का मात्र 0.3% प्रतिनिधित्व है। इसके बावजूद, भी मध्यम उद्यम MSME आधारित निर्यात में लगभग 40% का योगदान करते हैं।

मध्यम उद्यमों के समक्ष चुनौतियां

- पुरानी तकनीक: 82% मध्यम उद्यमों के पास अपने व्यावसायिक संचालन में एकीकृत करने हेतु उन्नत तकनीकें (उद्योग 4.0 - AI, IoT, आदि) नहीं हैं।
- कौशल विकास योजनाओं का कम उपयोग: 88% मध्यम उद्यम किसी भी सरकारी कौशल विकास या प्रशिक्षण योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं।
- वित्त-पोषण: विश्व बैंक की इंडियन MSME फाइनेंसिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 37% मध्यम उद्यम ही ऋण प्राप्त करने में सक्षम हैं।
- अनुपालन संबंधी बोझ: श्रम निरीक्षकों, स्वास्थ्य निरीक्षकों आदि सहित विविध प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले अनेक निरीक्षणों के कारण अनुपालन बोझ बढ़ गया है।
- अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास: केवल 22% मध्यम उद्यम अनुसंधान एवं विकास में शामिल हैं, जबकि बड़े उद्यमों में यह आंकड़ा 60% है।

आगे की राह - लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप

- आवश्यकतानुसार वित्तीय समाधान: इसमें उद्यम टर्नओवर से जुड़ी कार्यशील पूंजी वित्त-पोषण योजना की शुरुआत करना; बाजार दरों पर 5 करोड़ रुपये की क्रेडिट कार्ड सुविधा आदि शामिल हैं।
- उद्यम प्लेटफॉर्म के भीतर एक समर्पित उप-पोर्टल का निर्माण करना चाहिए, जिसमें योजना के बारे में पता लगाने, अनुपालन समर्थन और AI-आधारित सहायता शामिल होगी।
- मौजूदा उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रमों में मध्यम उद्यम-केंद्रित मॉड्यूल का एकीकरण करना।
- अन्य: इसमें अनुसंधान एवं विकास संवर्धन तंत्र, क्लस्टर-आधारित परीक्षण अवसरचना आदि शामिल हैं।



MSMEs का नया वर्गीकरण

प्रकार	निवेश		टर्नओवर	
	पहले	संशोधित	पहले	संशोधित
सूक्ष्म उद्यम	1 करोड़	2.5 करोड़	5 करोड़	10 करोड़
लघु उद्यम	10 करोड़	25 करोड़	50 करोड़	100 करोड़
मध्यम उद्यम	50 करोड़	125 करोड़	250 करोड़	500 करोड़

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने अधिकरणों के लिए एक 'केंद्रीकृत निरीक्षण तंत्र' स्थापित करने की सिफारिश की

CII ने अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 में संशोधन कर एक वैधानिक केंद्रीय निगरानी निकाय स्थापित करने की सिफारिश की है। इस निकाय का कार्य अधिकरणों के उद्देश्य, संरचना, दायरे और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होना चाहिए।

इस केंद्रीय निकाय की निम्नलिखित संभावित भूमिकाएं होगी:

- प्रदर्शन की निगरानी करना;
- खोज-सह-चयन समितियों से समन्वय करना;
- अधिकरणों की क्षमता में वृद्धि करना आदि।

अधिकरणों के लिए केंद्रीकृत निरीक्षण तंत्र की आवश्यकता क्यों है?

- विखंडित प्रशासनिक नियंत्रण: लगभग 16 केंद्रीय अधिकरण विविध मंत्रालयों के अधीन कार्य करते हैं। इससे मानकीकरण की कमी और कार्यप्रणाली में असंगतियां पैदा होती हैं।
- न्यायिक स्वतंत्रता: अधिकरणों में नियुक्तियों और सेवा शर्तों पर कार्यपालिका का नियंत्रण शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को कमजोर करता है। केंद्रीय निकाय नियुक्तियों को पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाकर अधिकरणों को कार्यपालिका के प्रभाव से बचा सकता है।
- एकरूपता: वर्तमान में, अधिकरणों की सदस्यता की संरचना, चयन प्रक्रिया या योग्यता में कोई एकरूपता नहीं है।
- अधिकरणों की कार्यकुशलता में सुधार: लंबित विवादों में फंसे बड़े राजकोषीय संसाधनों को मुक्त करने और व्यवसाय करने की सुगमता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है।
- उदाहरण के लिए- 31 दिसंबर 2024 तक केवल आयकर अपीलीय अधिकरण में ही ₹6.7 ट्रिलियन मूल्य के मामले लंबित थे, जो देश में सभी प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों का लगभग 57% था।
- न्यायिक निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने एल. चंद्र कुमार (1997) और मद्रास बार एसोसिएशन (2020) मामलों में एक केंद्रीय निगरानी निकाय की आवश्यकता पर बल दिया था।

अधिकरणों के बारे में

- अधिकरण कानून द्वारा स्थापित न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक संस्थाएं हैं।
- संवैधानिक प्रावधान: 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 323A और 323B जोड़े गए थे:
 - अनुच्छेद 323A: इसके तहत संसद को लोक सेवा से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार दिया गया है।
 - अनुच्छेद 323B: यह कुछ विशेष विषयों जैसे कि कराधान, भूमि सुधार आदि के लिए संसद या राज्य विधान-मंडलों को अधिकरण स्थापित करने की अनुमति देता है।
- महत्व: अधिकरण पारंपरिक न्यायालयों की तुलना में तीव्र न्यायनिर्णयन के लिए मंच प्रदान करते हैं। साथ ही, कुछ विषयों पर विशेषज्ञता के आधार पर निर्णय लेते हैं, जिससे मामलों का निपटारा अधिक प्रभावी होता है।

अन्य सुर्खियां



किलाउआ ज्वालामुखी

हवाई स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में दिसंबर 2024 के बाद, फिर से विस्फोट हुआ, जिससे इसमें से लावा के फव्वारे निकल रहे हैं।

- इस विस्फोट से राख, गैस और पेलेज हेयर (Pele's hair) नामक कांच जैसे ज्वालामुखीय फाइबर सहित विभिन्न ज्वालामुखीय पदार्थ निकले हैं।
- इसके प्रारंभिक खतरों में अत्यधिक मात्रा में ज्वालामुखी गैस का निकलना शामिल है। ये गैसें वायुमंडल के साथ प्रतिक्रिया करके वोग (ज्वालामुखी धुंध) बना सकती हैं, जो लोगों, जानवरों आदि को नुकसान पहुंचा सकता है।

किलाउआ ज्वालामुखी के बारे में

- अवस्थिति: यह अमेरिका स्थित हवाई द्वीप के दक्षिण-पूर्वी भाग में अवस्थित है।
- यह विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।
- यह हवाई वाल्केनोज़ नेशनल पार्क में स्थित है। इसके पास ही मोना लोआ नामक एक और बड़ा लेकिन कम सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है।
- ये दोनों शील्ड ज्वालामुखी हैं।
 - शील्ड ज्वालामुखी मिश्रित ज्वालामुखियों की तरह शंकाकार चोटियों वाले ऊंचे पर्वतों का निर्माण नहीं करते हैं।



भारत में शहद उत्पादन

प्रधान मंत्री ने बताया है कि पिछले एक दशक में देश में शहद के उत्पादन में 60% की वृद्धि हुई है।

भारत में शहद उत्पादन के बारे में

- उत्पादन: पिछले 11 वर्षों में भारत में शहद उत्पादन 70,000-75,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़कर लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन (60% वृद्धि) हो गया है।
 - भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा शहद उत्पादक देश है। दुनिया में चीन शहद का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है।
- प्रमुख शहद उत्पादक राज्य (2022-23): उत्तर प्रदेश (17%), पश्चिम बंगाल (16%), पंजाब, बिहार, राजस्थान आदि।
- निर्यात: भारत में शहद उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा निर्यात किया जाता है।
- प्रमुख निर्यात गंतव्य (2023-24): यू.एस.ए., यू.ए.ई., सऊदी अरब, कतर और लीबिया।



फारस की खाड़ी/ पर्शियन गल्फ

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पर्शियन गल्फ का नाम बदलकर 'अरेबियन गल्फ' या 'गल्फ ऑफ अरेबिया' करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया।

फारस की खाड़ी के बारे में

- यह हिंद महासागर का एक उथला सीमांत सागर है, जो अरब प्रायद्वीप और दक्षिण-पश्चिमी ईरान के मध्य स्थित है।
 - होर्मुज जलसंधि फारस की खाड़ी (पश्चिम) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर (दक्षिण-पूर्व) से जोड़ती है।
- इसकी सीमा ईरान, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत और इराक से लगती है।
- इस खाड़ी में टिग्रिस, यूफ्रेटिस और करुण नदियां गिरती हैं।
- यह समुद्री परिवहन, खासकर तेल के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है।



राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने NAPS के तहत दिए जाने वाले स्टैंडपेंड में 36% की वृद्धि की सिफारिश की है।

NAPS के बारे में

- इसे अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। इस योजना को वित्त वर्ष 2022-23 से NAPS-2 के रूप में संचालित किया जा रहा है।
- मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।
- उद्देश्य: प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।
- NAPS-2 एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। यह "कौशल भारत कार्यक्रम" की अम्ब्रेला योजना के तहत उप-घटकों में से एक है।
- NAPS-2 के तहत प्रशिक्षु के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष है। हालांकि कुछ चुनिंदा ट्रेड्स के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है।

INCOIS भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS)

INCOIS ने गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल के तटों पर ऊंची समुद्री लहरों की चेतावनी जारी की है।

INCOIS के बारे में

- उत्पत्ति: इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
 - यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ESSO) की एक इकाई है।
- मुख्यालय: हैदराबाद में स्थित है।
- प्रमुख कार्य: व्यवस्थित और केंद्रित अनुसंधान के जरिए सतत महासागरीय अवलोकन और उसमें निरंतर सुधार के माध्यम से समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदाय को महासागर संबंधी जानकारी और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना।
- अन्य INCOIS सेवाएं:
 - मछली पकड़ने के लिए संभावित क्षेत्रों (PFZ) की सलाह देना,
 - सुनामी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली,
 - महासागर स्थिति पूर्वानुमान (OSF),
 - कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम आदि।

पंचायत उन्नति सूचकांक (Panchayat Advancement Index)

पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया।

- पंचायत उन्नति सूचकांक पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में संकेतकों की संख्या को 516 से घटाकर 147 कर दिया गया है, जिससे डेटा की गुणवत्ता में सुधार, रिपोर्टिंग में आसानी और कार्रवाई योग्य जानकारी प्राप्त होती है।
- पंचायत उन्नति सूचकांक के बारे में
 - यह एक मल्टी-डोमेन और मल्टी-सेक्टरल सूचकांक है। इसका उपयोग पंचायतों के समय विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाता है।
 - यह LSDG से संबद्ध नौ विषयों पर आधारित है, जैसे महिला-अनुकूल पंचायत, जल-पर्याप्त पंचायत, आदि।

शुगर बोर्ड

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सभी संबद्ध स्कूलों को अपने परिसर में 'शुगर बोर्ड' स्थापित करने का निर्देश दिया है।

- यह कदम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की सिफारिश के बाद उठाया गया है, जिसने टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, आदि के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की है।
- टाइप 2 डायबिटीज तब होती है जब शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधक बन जाता है या पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है।
- टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को इम्यून सिस्टम नष्ट कर देता है।

शुगर बोर्ड के बारे में

- यह निम्नलिखित के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा, जैसे कि
 - दैनिक रूप से चीनी के सेवन की उचित मात्रा,
 - आमतौर पर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में चीनी की मात्रा (अस्वास्थ्यकर भोजन जैसे जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक आदि),
 - ज्यादा चीनी खाने से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी जोखिम आदि के बारे में।
- यह छात्रों को तथ्य और साक्ष्य के आधार पर खाद्य पदार्थों के बेहतर विकल्पों के बारे में शिक्षित करेगा।



रिजनरेटिव ब्रेकिंग

भारत ने रिजनरेटिव ब्रेकिंग से लैस 9000 हॉर्स पावर का पहला लोकोमोटिव (D-9 इंजन) लॉन्च किया।

रिजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में

- पारंपरिक इलेक्ट्रिक ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम में डायनेमिक ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें ट्रेन की गतिज ऊर्जा अपशिष्ट के रूप में मुख्य रूप से ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है।
- रिजनरेटिव ब्रेकिंग में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में करंट को रिवर्स कर दिया जाता है। इससे बिजली उत्पन्न होती है, जिसे बिजली वितरण प्रणाली में वापस भेजा जा सकता है।
- लाभ: यह ऊर्जा की कुल खपत को घटाने में मदद करता है, आदि।

सुर्खियों में रहे स्थल



मोजाम्बिक (राजधानी: मापुटो)

उत्तरी मोजाम्बिक में 25,000 से अधिक लोग तिहरे संकट के कारण पलायन कर चुके हैं। इस तिहरे संकट में सशस्त्र संघर्ष, बार-बार होने वाली चरम मौसमी घटनाएं और चुनाव के बाद फैली अशांति शामिल है।

भौगोलिक अवस्थिति

- अवस्थिति: यह देश अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। यह पूर्व में हिंद महासागर से लंबी तट रेखा साझा करता है।
 - मोजाम्बिक चैनल इसे मेडागास्कर द्वीप से अलग करता है।
- सीमावर्ती देश: तंजानिया (उत्तर में), मलावी और जाम्बिया (उत्तर-पश्चिम में), जिम्बाब्वे (पश्चिम में), दक्षिण अफ्रीका और इस्वातिनी (दक्षिण-पश्चिम में)।
- भौगोलिक विशेषताएं
 - प्रमुख नदियां: जाम्बेजी और लिम्पोपो (दोनों हिंद महासागर में गिरती हैं), रुवुमा आदि।
 - सबसे ऊंची चोटी: माउंट बिंगा (चिमोइओ हाइलैंड्स का हिस्सा)



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची